the new industrial and trade policies so as tc make them contribute significantly to the foreign exchange earnings of the country.

The table below gives the inflo\ and outflow of foreign exchange fo the years 1986-87, 1987-88, 1988-89 1989-90 for 50 industrial houses.

(Value Rs Crores

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-9
Foreign Exchange inflow . . .	539	1176	1993	2715
Foreign Exchange Outflow . . .	1058	4251	3024	387

The Statement at Annexure gives the details of the export performance cf the 50 select industrial houses for the year 1986-87 to 1989-90.

[See Appendix CLX, Annexure No. 48]

"तुलसी सदन पुस्तकालय" का कार्यकरण

1175. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्रीमती कैलाशपति :
श्री कपिल वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भाषाओं का एकमात्र पुस्तकालय "तुलसी सदन" गत दो वर्षों से बंद पड़ा है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) यह पुस्तकालय कब स्थापित किया गया था ;

(ग) इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं और प्रत्येक वर्ष खरीदी गयी पुस्तकों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार इस पुस्तकालय का विलय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के साथ करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां, व्यापक मरम्मत के लिए ।

(ख) 1974 में ।

(ग) लगभग 1,44,500 जिन्हें अनुपत्र में दर्शाया गया है । [देखिए परिशिष्ट CLX परिपत्र सं० 49]

(घ) जी, हां ।

(ङ) जिससे कि पुस्तकों का प्रयोग अधिक से अधिक हो सके ।

आंगनबाड़ी कर्मकारों की मजदूरी

1176. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अगस्त, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां दी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आंगनबाड़ी योजना के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं को अब तक सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस योजना के अन्तर्गत उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया गया है और उन्हें समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जा रही सुविधाओं के समान सभी सुविधाएं दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अधीन क्षेत्र में सक्रिय रूप से काय कर रही महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कु० ममता बैनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना (आई सी डी एस) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा दो श्रेणियों के कार्यकर्ता रखे जाते हैं—स्टाफ जिसमें कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अपर/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर (मुख्य-सेविकाएं) तथा राज्य स्तर पर, जिला स्तर, ब्लाक स्तर और परियोजना स्तर पर अनुसचिवीय स्टाफ आता है। दूसरी श्रेणी में निचले स्तर के कार्यकर्ता अर्थात् आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आती हैं। वे अंशकालिक, अवैतनिक, स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं और सामान्यतः उसी गांव से लिए जाते हैं जहां आंगन-वाड़ी केन्द्र स्थित होता है। दोनों श्रेणियों के स्टाफ की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा की जाती है।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना सामुदायिक सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय से ली गई अंशकालिक, स्वयंसेवी और अवैतनिक कार्यकर्ता होते हैं और उन्हें सरकारी कर्मचारी माने जाने से सामुदायिक सहभागिता का सिद्धान्त ही समाप्त हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ियों में चार घंटे काम करती हैं और उन्हें प्रति दिन आधा घंटा घरों का दौरा करना होता है। सहायिकाओं के लिए गृह-दौरे करना अपेक्षित नहीं है।

Overinvoicing in import of drugs

1177. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that duty free import of bulk drugs and formulations is giving rise to overin voicing;

(fo) if so, what is the number of such instances that have come to the notice of his Ministry;

(c) what is the rationale behind duty free import of the products which are not price controlled;

(d) what are the names of finished medicines and bulk drugs which are exempted from price control and where his Ministry has either allowed exemption from or concession of customs duty during the last three years;

(e) whether it is a fact that hi* Ministry did not agree to certain proposals in the drug sector for hike in duties of bulk drugs and intermediates which are produced from basic stage and finished medicines being produced, indigenously;

(f) if so, what are the names of such items and the reasons for rejecting the proposal; and

(g) what is the total loss in foreign exchange due to this lapse?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Information regarding the number of instances of overin voicing of imports of duty free bulk drugs and formulations is not readily available. The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Exemption from import duty is extended to bulk drugs and intermediates so as to encourage indigenous production from the more basic